**वित्त मंत्रालय**
**लोक उद्यम विभाग**
**मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2023 माह हेतु डीपीई की मासिक उपलब्धियां**

**1. कैपेक्स लक्ष्य:**

जुलाई, 2023 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य वाले) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 7 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। ₹7.33 लाख करोड़ (बजट अनुमान) के अनुमानित व्यय की तुलना में, उपलब्धि ₹2.57 लाख करोड़ (लगभग) अर्थात् दिनांक 31.7.2023 तक लगभग 35.10% था। जबकि यह पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022-2023 में इसी अवधि में 27.89% था।

**2. सीपीएसईज़ का संचालन:**

(i) दिनांक 19.07.2023 को व्यय विभाग की 'विवाद से विश्वास-II योजना' के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें व्यय विभाग ने सभी प्रतिभागियों मंत्रालयों/विभागों के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

(ii) विभिन्न सीपीएसईज़ के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 05/7/2023 को सर्च समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। सर्च समिति ने एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए 17 नामों की सिफारिश की थी।

(iii) लोक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को अनुसूची 'ख' से 'क' में स्तरोन्नत किया गया था।

(iv) ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 27/7/2023 को आयोजित की गई थी।

(v) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 27/7/2023 को आयोजित की गई थी।

(vi) बेल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड (बीईएलओपी) को अनुसूची 'घ' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के रूप में प्रारंभिक श्रेणीकरण और प्रबंध निदेशक के पद के सृजन के प्रस्ताव पर लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के परामर्श से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में विचार किया गया था और इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

(vii) इरकॉन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 28 जुलाई 2023 को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक आयोजित की गई थी।

**3. वेतन संशोधन और वेतन अधिसूचनाएं:**

डीपीई ने आईडीए पैटर्न वेतनमान 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 के दिनांक 07.7.2023 के कार्यालय ज्ञापन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों के लिए दिनांक 01.7.2023 से देय डीए के लिए आदेश जारी किए।

**4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

(i) डीपीई और यूनिसेफ ने दिनांक 10 जुलाई 2023 को सहयोग के एक पत्र का आदान-प्रदान किया। सहयोग का उद्देश्य सीएसआर फंड के प्रभावी और रणनीतिक उपयोग और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए यूनिसेफ को डीपीई के साथ 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में काम करने की सुविधा प्रदान करना है।

**5. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:**

(i) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 93 सीपीएसईज़ के संबंध में समझौता ज्ञापनों का मसौदा जारी किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 26 सीपीएसईज़ के संबंध में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया और ऑनलाइन एमओयू डैशबोर्ड के माध्यम से जारी किया गया। इनमें से 11 सीपीएसईज़ के समझौता ज्ञापनों पर ई-हस्ताक्षर किए गए।

(iii) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए 38 सीपीएसईज़ के संबंध में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

**6. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स:**

(i) सीपीएसईज़ के एनओडी के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान और एनईजीडी के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, डीपीई की अध्यक्षता में दिनांक 14/7/2023 को एक बैठक आयोजित की गई।

(ii) नमक आयुक्त संगठन (एससीओ) के युक्तिकरण और इसकी भूमि के निपटान के लिए सचिव की समिति (सीओएस) की बैठक दिनांक 31.7.2023 को आयोजित की गई थी।

(iii) डीपीई ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित निम्नलिखित प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं: -

(क) संशोधित झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर कोयला मंत्रालय द्वारा परिचालित ईएफसी नोट का मसौदा

(ख) 'राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी सहायता' योजना पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित एसएफसी नोट का मसौदा

**7. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:**

(i) 2023-24 (जुलाई, 2023 तक) के दौरान एमएसई से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद अनिवार्य 25% (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार) की तुलना में 40% थी।

(ii) जुलाई, 2023 तक जीईएम के माध्यम से सीपीएसईज़ द्वारा खरीद 42,510 करोड़ रुपये थी, जो पिछले साल की तुलना में 74% की वृद्धि दर्शाती है।

**8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति**:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 113 मामले रिपोर्ट/पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 24 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 66 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समितियों के पास हैं। शेष 23 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी संवीक्षा और अनुमोदन के लिए हैं।

*********